



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 08

30 माघ 1941 (श0)
पटना, बुधवार, ———
19 फरवरी 2020 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-21	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9-विज्ञापन ---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 22-22	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 23-23
भाग-4-बिहार अधिनियम ---	पुरक ---
	पुरक-क 24-32

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

3 फरवरी 2020

सं० 05/स्था० (DTO)-30/2013 (खण्ड-1)/1033—श्री रजनीश लाल (बि०प्र०से०), जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल (अतिरिक्त प्रभार जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 05/स्था० (DTO)-30/2013 (खण्ड-1)/1034—श्री फिरोज अख्तर (बि०प्र०से०), जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 05/स्था० (DTO)-30/2013 (खण्ड-1)/1035—श्री रवि कुमार (बि०प्र०से०), जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ, उप—सचिव।

13 फरवरी 2020

सं० 05/स्था०-146/2007/1276—आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दुर्गा नन्द झा, बि०प्र०से०, आयुक्त के सचिव, दरभंगा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ, उप—सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

28 जनवरी 2020

सं० 2/स्था० (12) 01/2019-279—पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागीय अधिसूचना सं०-769—सह—पठित ज्ञापक—770 दिनांक 07.03.2019 द्वारा डा० प्रियम्बदा की नियुक्ति बिहार पशु चिकित्सा सेवा के मूल कोटि के पद पर करते हुए भ्रमणशील पशु चिकित्सा, बेलागंज, गया के पद पर पदस्थापित किया गया। तदालोक में उनके द्वारा दिनांक 18.03.2019 को योगदान करते हुए प्रभार ग्रहण किया गया।

2. डा० प्रियम्बदा द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों तथा पारिवारिक कारणों से दिनांक 27.03.2019 को पद से त्यागपत्र समर्पित करने का अभ्यावेदन दिया गया।

3. उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-2520 दिनांक 14.08.2019 द्वारा डा० प्रियम्बदा के त्यागपत्र को स्वीकृत करने का निर्णय संसूचित किया गया।

4. डा० प्रियम्बदा द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन मगध क्षेत्र, गया के माध्यम से एक अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा यह अंकित किया गया कि व्यक्तिगत परेशानियों में व्यस्त रहने के कारण पूरी तरह असहाय होकर संघर्षरत थी जिससे हताशा में उनके द्वारा पद से त्यागपत्र का अभ्यावेदन दे दिया गया जिसके लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं। अभ्यावेदन में उनके द्वारा उनके त्यागपत्र के आवेदन को निरस्त करने तथा अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध भी किया गया।

5. डा० प्रियम्बदा के उक्त अभ्यावेदन के आलोक में विभाग द्वारा स्वीकृत उनके त्यागपत्र/ इस्तीफा को अस्वीकृत/रद्द करने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग का मतव्य प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभाग द्वारा मामले की समीक्षा तथा समीक्षोपरान्त डा० प्रियम्बदा के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक

विचार करते हुए उनके त्याग-पत्र की स्वीकृति संबंधी अधिसूचना सं०-2520 दिनांक 14.08.2019 को निरस्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में डा० प्रियम्बदा तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बेलागंज गया की त्याग-पत्र की स्वीकृति संबंधी विभागीय अधिसूचना सं०-2520 दिनांक 14.08.2019 को निरस्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता "प्रेम", अवर सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

7 फरवरी 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (विविध) लो०का०-08/2018-456427—श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, छौड़ादानों, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध श्री ठाकुर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किये गये यात्रा भत्ता विपत्र/अभिभ्रव के समायोजन की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करने के संबंध में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 75/स्था० दिनांक 17.07.2019 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आरोप-पत्र पर श्री गुप्ता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

उक्त संदर्भ में श्री गुप्ता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि अभिभ्रव/विपत्र के समायोजन हेतु ससमय कार्रवाई नहीं की गयी एवं कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरती गयी।

अतएव श्री गुप्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत 'वर्ष 2015-16 के लिए निन्दन' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री गुप्ता के सेवा पुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कैवल तनुज, अपर सचिव।

6 फरवरी 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (भा०) भा०-05/2019-456316—श्रीमती छाया कुमारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहपुर, भागलपुर के विरूद्ध अपने दायित्वों का निर्वहन कार्यालय से नहीं कर आवास से करने, लंबे अवकाश से वापस आने के बावजूद भी कार्यालय के अभिलेख अपने पास अनाधिकृत रूप से रखने, कार्यालय लैपटॉप निजी व्यवहार के उद्देश्य से अपने पास रखने, पद का दुरुपयोग एवं अनुशासनहीनता बरतने के लिए जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-485 दिनांक 19.04.2015 द्वारा आरोप पत्र 'क' प्राप्त हुआ।

आरोप पत्र में धारित आरोपों के आलोक में श्रीमती छाया कुमारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

उक्त आरोप पत्र में गठित आरोप एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती कुमारी के द्वारा कार्यालय के अभिलेख एवं अन्य चीजों का प्रभार देते समय लैपटॉप का प्रभार नहीं दिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त के निरीक्षण प्रतिवेदन में मामला उजागर होने के उपरान्त उनके द्वारा लैपटॉप का प्रभार दिया गया। अतः श्रीमती छाया कुमारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहपुर, भागलपुर, सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार सरकारी लैपटॉप लंबे समय तक अपने पास रखने की दोषी हैं।

अतः श्रीमती छाया कुमारी को 'चेतावनी' की सजा दी जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रविष्टि श्रीमती कुमारी के सेवा पुस्त में की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कैवल तनुज, अपर सचिव।

12 फरवरी 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (द०) दर०-02/2017-456864—श्री शशि प्रकाश, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा, दरभंगा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी दरभंगा के पत्रांक-1957 दिनांक 14.12.2017 द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लंबित मामलों का

निष्पादन नहीं करने के आरोप में आरोप प्रपत्र 'क' विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त आरोप प्रपत्र 'क' में वर्णित आरोपों पर श्री शशि प्रकाश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी दरभंगा से प्राप्त मंतव्य की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री शशि प्रकाश अंचलाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में थे। मूल पदस्थापन प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में रहने एवं अतिरिक्त कार्य भार के कारण उक्त प्रभार वाले मामले के अनुपालन में विलम्ब हुआ। तथापि प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर चार मामले लंबित पाये गये।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री शशि प्रकाश, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा, दरभंगा सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ढाका, पूर्वी चम्पारण को चेतावनी देते हुए भविष्य में कार्य के प्रति सचेष्ट रहने का निदेश दिया जाता है।

आदेश से,
कैवल तनुज, अपर सचिव।

12 फरवरी 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (ति०) मु०-03/2018-456886—श्री रत्नेश्वर कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पारू, मुजफ्फरपुर के सरकारी आवास से दिनांक 15.01.2018 को कुख्यात फरार अपराधी तुलसी राय को नशे की हालत में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-32 की उपधारा (3) के तहत अपराध कारित करने के लिए उत्तरदायी होने एवं उक्त अधिनियम की धारा-37 की उपधारा (घ) एवं धारा-38 की उपधारा-(2) के तहत नजदीकी उत्पाद अथवा पुलिस पदाधिकारी को सूचित नहीं करने जैसे गंभीर आरोप के लिए श्री कुमार के विरुद्ध जिला पदाधिकारी के पत्रांक-818 दिनांक 06.03.2018 द्वारा विहित प्रपत्र में प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(क) के तहत श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना सं०-360183 दिनांक 15.03.2018 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-383692 दिनांक 09.08.2018 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/निष्कर्ष प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

श्री रत्नेश्वर कुमार ग्रामीण विकास विभाग (मुख्यालय) में योगदान समर्पित करेंगे। न्यायालयीय प्रक्रिया में न्यायालय के निर्णयोपरान्त विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

उक्त आदेश पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
कैवल तनुज, अपर सचिव।

7 फरवरी 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (ति०) पू०च०-03/2017-456508—श्री रमेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बंजरिया, पूर्वी चम्पारण के विरुद्ध सी०डब्लू०जे०सी० नं० 197/16 श्री ललन साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में जिला विधि शाखा द्वारा निदेश दिये जाने के बावजूद प्रतिशपथपत्र दायर करने में एक वर्ष का बिलम्ब करने के संबंध में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-133 दिनांक 03.06.2017 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोप पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र एवं श्री कुमार के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट है कि विधि शाखा द्वारा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त इन्हें लगातार अनुश्रवण करना चाहिए था। इस हद तक कर्तव्य में चूक हुई है।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमार को भविष्य में सचेष्ट रहने का निदेश देते हुए आरोप से मुक्त किया जाता है।

आदेश से,
कैवल तनुज, अपर सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

**अधिसूचनाएं
29 जनवरी 2020**

सं० भा०व०से०(स्था०)-12/2019-337/प०व०—श्री आलोक कुमार, भा०व०से०, (BH:2007), सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर-13) में दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

सं० भा०व०से०(स्था०)-12/2019-338/प०व०—श्री एस. सुधाकर, भा०व०से०, (BH:2007), वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर-13) में दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

सं० भा०व०से०(स्था०)-12/2019-339/प०व०—श्री सुधीर कुमार, भा०व०से०, (BH:2007), वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर-13) में दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

सं० भा०व०से०(स्था०)-12/2019-340/प०व०—श्री सुधीर कुमार कर्ण, भा०व०से०, (BH:2007), वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर-13) में दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

29 जनवरी 2020

सं० भा०व०से०(स्था०)-12/2019-335/प०व०—श्री नन्द किशोर, भा०व०से०, (BH:2006), निदेशक, बागवानी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-13 ए रूपये 1,31,100-2,16,600) में प्रोन्नति दी जाती है।

2. भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत श्री नन्द किशोर द्वारा वर्तमान धारित पद (निदेशक, बागवानी, कृषि विभाग, बिहार, पटना) को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए वन संरक्षक कोटि के समकक्ष घोषित किया जाता है।

सं० भा०व०से०(स्था०)-12/2019-336/प०व०—श्री एस. कुमारसामी, भा०व०से०, (BH:2006), वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-13 ए रूपये 1,31,100-2,16,600) में प्रोन्नति दी जाती है।

2. इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

5 फरवरी 2020

सं० वनभूमि-75/2018-181(ई०)/प०व०ज०प०—माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर W.P. (c) संख्या-202/95: टी०एन० गोदावर्मन तिरूमूलपाद बनाम भारत संघ व अन्य में दायर आई०ए० संख्या-5891/2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2019 को पारित आदेश में कैम्पा निधि से संचालित योजनाओं एवं राशि के व्यय के अनुश्रवण हेतु राज्य सरकार के स्तर पर स्थापित अथवा प्रस्तावित व्यवस्था के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है। इस न्यायादेश के अनुपालन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के पत्रांक-910, दिनांक 31.12.2019 द्वारा राज्य स्तर पर अनुश्रवण समिति के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। तदालोक में कैम्पा निधि से आवंटित राशि के व्यय एवं कार्यों के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत् गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|------------|
| i. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना। | :- अध्यक्ष |
| ii. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना। | :- सदस्य |
| iii. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना। | :- सदस्य |
| iv. मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन | :- सदस्य |

- | | | |
|-------|--|---------------|
| v. | मुख्य वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी | :- सदस्य |
| vi. | निदेशक, हरियाली मिशन | :- सदस्य |
| vii. | वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन | :- सदस्य सचिव |
| viii. | राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा दो मनोनीत सदस्य | :- सदस्य |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

31 दिसम्बर 2019

सं० वन क्षेत्र पदा०-10/2018-4826/प०व०ज०प०—श्री ब्रज किशोर, बि०व०से०, तत्कालीन सहायक वन संरक्षक, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ सम्प्रति उप वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, भागलपुर के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-2861, दिनांक 09.10.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं इस विभागीय कार्यवाही में आरोपों की जाँच करते हुए श्री एस० चन्द्र शेखर, भा०व०से० को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-152, दिनांक-30.03.2019 एवं पत्रांक-1155, दिनांक 03.10.2019 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री ब्रज किशोर, बि०व०से० के विरुद्ध गठित पाँच आरोपों में आरोप सं०-2, 3, 4, 5 यथा दूरभाष पर झुठी सूचना देकर उच्चाधिकारी को गुमराह करना/वन्यप्राणी संरक्षण (कर्तव्य) में घोर लापरवाही बरतना/विभाग की छवि धूमिल करना तथा कर्तव्य पर घोर लापरवाही बरतना को अंशतः प्रमाणित पाया गया है। विभागीय पत्रांक-4003, दिनांक-05.11.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति श्री ब्रज किशोर, बि०व०से० को भेजते हुए उनका लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है।

जाँच प्रतिवेदन एवं श्री ब्रज किशोर द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत श्री ब्रज किशोर बि०व०से० पर निम्नांकित शास्ति अधिरोपित की जाती है :—“निन्दन की सजा, जिसकी प्रविष्टि इनके वर्ष-2017-18 की चारित्रि में की जाय।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

29 जनवरी 2020

सं० भा०व०से० (स्था०) 15/2019-341/प०व०—श्री रविशंकर कुमार भा०व०से०(BH:95) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक लीव रिजर्व में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

सं० भा०व०से० (स्था०) 15/2019-342/प०व०—श्री संजय कुमार सिन्हा भा०व०से०(BH:2000) मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम लि०, पटना, सदस्य सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना) अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक-सह-निदेशक, हरियाली मिशन, बिहार, पटना (दिनांक 01.02.2020 के प्रभाव से) एवं प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लि० तथा बिहार सोलमेंट एण्ड केमिकल्स लि०, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० भा०व०से० (स्था०) 15/2019-343/प०व०—श्री अभय कुमार द्विवेदी भा०व०से०(BH:2000) मुख्य वन संरक्षक-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन एवं विकास, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री द्विवेदी मुख्य वन संरक्षक-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार, पटना तथा वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० भा०व०से० (स्था०) 15/2019-344/प०व०—श्री के० के० अकेला, भा०व०से०(BH:2000) मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन एवं विकास, बिहार पटना को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० भा०व०से० (स्था०) 15/2019-345/प०व०—श्री सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०(BH:2001) निदेशक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना (अतिरिक्त प्रभार-वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) अगले आदेश तक वन संरक्षक, वन्यजीव अंचल, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० भा०व०से० (स्था०) 15/2019-346/प०व०—श्री कमलजीत सिंह, भा०व०से०(BH:2004) वन संरक्षक, वन्यजीव अंचल, पटना (अतिरिक्त प्रभार-वन संरक्षक-सह-अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक-सह-अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० भा०व०से० (स्था०) 15/2019-347/प०व०—श्री एस० कुमारा सामी, भा०व०से०(BH:2006) वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक, पूर्णिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० भा०व०से० (स्था०) 15/2019-348/प०व०—सुश्री रुचि सिंह, भा०व०से०(BH:2017) संलग्न पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल बिहारशरीफ को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

6 दिसम्बर 2019

सं० योजना बजट-09/2018-4504/प०व०—राज्य में बाँस के रोपण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों, विशेषज्ञों, उद्यमियों तथा कृषकों के माध्यम से इसके उपयोग के विभिन्न आयामों/सम्भावनाओं को अधिकाधिक लोकप्रिय तथा जनसधारण के लिए उपयोगी बनाने के निमित्त राज्य स्तर पर केन्द्र से समन्वय स्थापित करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-2777 दिनांक 28.09.2018 द्वारा राज्य स्तर पर कार्यकारी समिति गठित है।

कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार (राष्ट्रीय बाँस मिशन संभाग) के पत्रांक—F.N.-44-22/2018-NBM (PT.2) (FTS 75150) दिनांक 28.08.2019 द्वारा प्राप्त दिशा—निर्देश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-2777 दिनांक 28.09.2018 द्वारा गठित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता है :-

(1)	प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
(2)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना	सदस्य
(3)	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(5)	प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(7)	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(8)	प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(9)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	डॉ. ए.के. चौधरी, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, पी.टी.सी. लैब, टी.एन.बी. कॉलेज, भागलपुर	सदस्य
(11)	श्री अमरेश चौधरी (कृषक), ग्राम—भवारा कोठी, प्रखण्ड—कटिहार, जिला—कटिहार	सदस्य
(12)	राज्य मिशन निदेशक (मुख्य वन संरक्षक—सह—निदेशक, हरियाली मिशन, बिहार)	सदस्य सचिव

2. इस समिति का कार्य एवं दायित्व :-

(क) यह समिति राज्य के वार्षिक कार्य योजना को राष्ट्रीय बाँस मिशन के कार्यकारी पर्वद को भेजने के पूर्व अनुमोदित करेगी।

(ख) यह समिति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी।

3. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-2777 दिनांक-28.09.2018 द्वारा गठित कार्यकारी समिति को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

12 दिसम्बर 2019

सं० 02/बि०व०से० (आ०)-08/2018-4627/प०व०—श्री ब्रज किशोर, बि.व.से., तत्कालीन सहायक वन संरक्षक, भभुआ सम्प्रति उप वन संरक्षक, कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-128 दिनांक 10.01.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं इस विभागीय कार्यवाही में आरोप की जाँच हेतु श्री एस. चन्द्रशेखर, भा.व.से., को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी के कार्यालय ज्ञापांक-1136 दिनांक 28.09.2019 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री ब्रज किशोर, बि.व.से., के विरुद्ध गठित छः आरोपों में आरोप संख्या-5 एवं 6 यथा “बिना किसी सूचना एवं सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के मुख्यालय से गायब रहना तथा इस संबंध में गलत/झूठी सूचना देना एवं विभाग की गरिमा को भंग करना तथा उच्चाधिकारी से मिडिया के समक्ष गाली-गलौज एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग कर अनुशासनहीनता कर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम संख्या-3 (1)(iii) तथा 9 के विरुद्ध आचरण करना” को प्रमाणित पाया गया है। विभागीय पत्रांक-3799 दिनांक 21.10.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति श्री ब्रज किशोर, बि.व.से. को भेजते हुए उनका लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किया गया।

जाँच प्रतिवेदन एवं श्री ब्रज किशोर द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा श्री ब्रज किशोर, बि.व.से., को निम्नांकित शास्ती अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :-

“निन्दन की सजा, जिसकी प्रविष्टि इनके वर्ष 2018-19 की चारित्रि में की जाय।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

7 फरवरी 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-01/2020-392/वा०कर—अब्दुल रशीद अंसारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया (60वीं से 62वीं बैच) को उनके पूर्व के विभाग बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में उनके अनुरोध पर पुनः वापस जाने हेतु अधिसूचना निर्गमन की तिथि से बिहार वित्त सेवा से विधिवत विरमित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

12 फरवरी 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-45/2008-432/वा०कर—श्री प्रभात कुमार वर्मा, राज्य-कर अपर आयुक्त (अपील), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को दिनांक 01.02.2020 के प्रभाव से राज्य-कर अपर आयुक्त (अपील), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

12 फरवरी 2020

सं० 6/गो०-34-06/2016-436/वा०कर—श्री दुर्गा प्रसाद मंडल, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बेतिया अंचल, बेतिया की सेवानिवृत्ति के उपरान्त बेतिया अंचल में पदस्थापित वरीय पदाधिकारी श्री अखिलेश कुमार मिश्र, राज्य-कर उपायुक्त को अगले आदेश तक अंचल प्रभारी, बेतिया का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

12 फरवरी 2020

सं० 6/गो०-34-06/2016-437/वा०कर—श्री धर्म देव कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त, सहरसा अंचल, सहरसा को श्री कमल किशोर चौधरी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त के उपार्जित अवकाश की अवधि दिनांक 04.02.2020 से 04.03.2020 तक के लिए अंचल प्रभारी, सहरसा के पद पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

14 फरवरी 2020

सं० 6/गो०-34-03/2019-472—वाणिज्य-कर विभाग में 56वीं० से 59वीं० बैच के नवनि्युक्त परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त श्री अमरेश कुमार, गृह जिला-पटना को अगले आदेश तक राज्य-कर सहायक आयुक्त, गोपालगंज अंचल, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अमरेश कुमार नवपदस्थापित स्थान पर सात दिन के अन्दर योगदान करेंगे एवं गोपालगंज अंचल से ही निर्धारित तिथि को नासिन एवं बिपार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, अपर सचिव।

शिक्षा विभाग**अधिसूचना****3 फरवरी 2020**

सं० 3/आ०1-66/2018/74—श्री राज किशोर सिंह, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण (छापरा) सम्प्रति-जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया के विरुद्ध ध्यानाकर्षण के माध्यम से बिहार विधान परिषद में प्रतिवेदित आरोपों यथा-नियम विपरीत कार्य करने, शिक्षकों के मनचाहे स्थानों पर स्थानांतरण/पदस्थापन कर अवैध राशि की उगाही करने/टी०ई०टी० परीक्षा में परीक्षार्थियों को पास कराने हेतु छपरा के बाहर के शिक्षकों को मनचाहे केन्द्रों पर तैनाती करने, दागी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मांझी को उक्त परीक्षा का केन्द्राधीक्षक बनाकर टी०ई०टी० अभ्यर्थियों को पास कराया गया जिनमें इनकी बहु भी थी, की जाँच विभागीय स्तर से गठित जाँच कमिटी से करायी गयी।

2. जाँच कमिटी के प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सिंह के विरुद्ध आरोप प्रपत्र-‘क’ गठित कर बचाव अभिकथन की माँग की गयी। जाँच कमिटी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह द्वारा स्थानांतरण/पदस्थापन में सावधानी एवं पारदर्शिता नहीं बरतने के प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिंह को निम्न लघु दण्ड संसूचित करते हुए मामले को समाप्त किया जाता है:-

(i) आरोप वर्ष-2017-18 के लिए “निन्दन”।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

श्रम संसाधन विभाग**आदेश****4 फरवरी 2020**

सं० 5/आ०एल०-40-01/2018 श्र०सं०-437—श्री कुमुद रंजन, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, गिद्धौर, जमुई सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेतिया सदर दिनांक 22.07.2014 को चिकित्सीय जांच हेतु तीन दिनों का अवकाश दिये जाने हेतु श्रम अधीक्षक, जमुई को आवेदन समर्पित किया। पुनः स्पीड-पोस्ट के माध्यम से “बिना छुट्टी की अवधि का उल्लेख किये बिना” अवधि विस्तार हेतु आवेदन, श्रम अधीक्षक, जमुई के कार्यालय में समर्पित किया। परन्तु उक्त तिथि के बाद श्री रंजन द्वारा श्रम अधीक्षक, जमुई के कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया।

तदालोक में विभागीय पत्रांक-236 दिनांक 08.01.2018 द्वारा श्री रंजन को निलम्बित करते हुए श्रमायुक्त कोषांग में इनका मुख्यालय निर्धारित किया गया। श्री रंजन द्वारा उक्त निर्धारित मुख्यालय में दिनांक 09.01.2018 को अपना योगदान समर्पित किया गया। विभागीय आदेश ज्ञापांक-448 दिनांक 16.01.2018 द्वारा श्री रंजन को निलम्बन से मुक्त करते हुए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेतिया सदर के पद पर पदस्थापित किया गया। सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर, मुख्यालय बेतिया के पत्रांक-609 दिनांक 19.05.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री रंजन, तबीयत खराब का हवाला देते हुए आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर दिनांक 31.03.2018 से अभी तक लगागार मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। विभागीय पत्रांक-4594 दिनांक 22.06.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से श्री रंजन का मेडिकल बोर्ड गठित कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर, मुख्यालय बेतिया के पत्रांक-1032 दि०-18.08.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि श्री रंजन के चिकित्सीय परीक्षण हेतु अर्सेनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प० चम्पारण द्वारा दिनांक 13.08.2018 को चिकित्सा परिषद् का गठन किया गया, परन्तु दिनांक 12.08.2018 को श्री रंजन द्वारा सूचित किया गया कि वे लम्बी यात्रा कर बेतिया आकर चिकित्सीय परीक्षण कराने में असमर्थ हैं।

श्रम अधीक्षक, जमुई के पत्रांक-389 दिनांक 17.07.2018 द्वारा बिना आवेदन स्वीकृत करायें अपने मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में श्री रंजन के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया

गया। श्रम अधीक्षक, जमुई द्वारा विभाग को प्रेषित श्री रंजन के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में जुलाई, 2014 से 7 जनवरी, 2018 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण वेतन निकासी नहीं किये जाने का उल्लेख है। विभागीय पत्रांक-6127 दिनांक 16.08.2018 द्वारा श्री रंजन से आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु उनका जबाब अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक 30.10.2018 को समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए उनसे आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु उनका जबाब अप्राप्त रहा। तदालोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-8240 दिनांक 28.12.2018 द्वारा श्री रंजन के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की गयी जिसमें श्री रोहित राज सिंह, सहायक श्रमायुक्त, मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-74 दिनांक 09.07.2019 द्वारा प्रासंगिक मामले में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा मामले की सुनवाई विभिन्न तिथियों को निर्धारित कर आरोप के संबंध में आरोपी पदाधिकारी से बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने की मांग की। परन्तु श्री रंजन उक्त निर्धारित सुनवाई में अनुपस्थित रहे एवं संचालन पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते रहे। साथ ही उनके द्वारा कोई भी लिखित मंतव्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त स्थिति के आलोक में श्री रंजन को विभागीय कार्रवाई के प्रति कोई रुचि नहीं लेने के कारण संचालन पदाधिकारी द्वारा एक पक्षीय निर्णय लेते हुए इनके विरुद्ध लगे आरोपों को प्रमाणित पाया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-3363 दिनांक 01.08.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-18(3) के तहत जांच प्रतिवेदन पर आरोपी पदाधिकारी से अभ्यावेदन की मांग की गयी।

परन्तु उक्त संबंध में श्री रंजन का आवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक 28.09.2019 को समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए जांच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। परन्तु श्री रंजन का जबाब अभी तक अप्राप्त रहा है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के सम्यक जाँचोपरांत पाया गया कि श्री रंजन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेतिया सदर को अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय से अनुपस्थित हैं। बार-बार निदेश दिये जाने के बाद भी वे लगातार रूप से अनुपस्थित रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि उनकी सरकारी सेवा में कोई रुचि नहीं है। वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के भाग-V नियम-14 (Xi) के आलोक में निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है:-

1. श्री कुमुद रंजन, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, गिद्धौर, जमुई सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेतिया सदर, (जन्म तिथि-04.01.1979) को "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी", का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश से,
धर्मेन्द्र सिंह, श्रमायुक्त।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचनाएं
13 फरवरी 2020

सं० एल/एच०जी०-1501/2005-1493—वित्त विभाग की संकल्प ज्ञापांक-7566, दिनांक-14.07.2010 के आलोक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा संवर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारी को बिहार कर्मचारी सेवा शर्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010" के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित तिथि से कॉलम-5 में उल्लिखित वेतनमान में तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एम०ए०सी०पी०) की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०	नाम/पदनाम/वेतनमान	जिला समादेष्टा के पद पर नियुक्ति की तिथि	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के फलस्वरूप अनुमान्य वेतन लेवल
1	2	3	4	5
1	श्री विमल कुमार शांडिल्य, वरीय जिला समादेष्टा, वेतन लेवल-12	20.10.1989	20.10.2019	वेतन लेवल-13

2. इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

3. स्वीकृत एम०ए०सी०पी० में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ संबंधी आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा तदनुसार उन्हें भुगतान की गयी राशि का समायोजन किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।

13 फरवरी 2020

सं० एल/एच०जी०-1501/2005-1494—वित्त विभाग की अधिसूचना सं०-6068, दिनांक 13.06.2013 के आलोक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना सं०-13890, दिनांक 21.09.2011 द्वारा दिनांक 01.01.2009 से प्रदत्त प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) को रद्द करते हुए बिहार कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन (संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित तिथि से कॉलम-5 में उल्लिखित वेतनमान में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ए०सी०पी०) की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०	नाम/पदनाम/वेतनमान	जिला समादेष्टा के पद पर नियुक्ति की तिथि	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के फलस्वरूप अनुमान्य वेतनमान
1	2	3	4	5
2	श्री जयंत प्रताप सिंह जिला समादेष्टा पी०बी०-3 + ग्रेड पे ₹6600	02.05.1997	02.05.2009	पी०बी०-3 + ग्रेड पे ₹6600
3.	श्री राणा अमरेन्द्र कुमार दीपक जिला समादेष्टा पी०बी०-3 + ग्रेड पे ₹6600	02.05.1997	02.05.2009	पी०बी०-3 + ग्रेड पे ₹6600
4.	श्री अनुज कुमार, जिला समादेष्टा पी०बी०-3 + ग्रेड पे ₹6600	02.05.1997	02.05.2009	पी०बी०-3 + ग्रेड पे ₹6600

2. इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

3. स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ संबंधी आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि का समायोजन किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

11 फरवरी 2020

सं० 1/प्रति.05-01/2019-165—श्री दीपक आनन्द भा०प्र०से०, अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए निदेशक, पुरातत्व, बिहार के पद का प्रभार सौंपा जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
तारानन्द महतो वियोगी, उप-सचिव।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचनाएं

4 जनवरी 2019

सं० 8/आ०(राज०उ०)-02-31/2015-37—श्री सरोज कुमार, तत्का० प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं०-110/2015 दिनांक 23.12.2015 दर्ज किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-333 दिनांक 19.01.2016 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सं०-3664 दिनांक 2.8.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया है। श्री कुमार के दिनांक 31.08.2016 को सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.08.2016 से उन्हें निलम्बन मुक्त किया जाता है।

2. श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

4 जनवरी 2019

सं० 8/आ०(राज० नि०)-1-34/2014/38—श्री अजय कृष्ण मिश्र, तत्का० सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया (निलंबित) के विरुद्ध अपने सेवाकाल में पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक चल अचल सम्पत्ति अर्जित करने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल आचरण करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-5479 दिनांक 16.12.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-95 दिनांक 01.02.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप सं०-01 एवं 02 को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-549 दिनांक 16.02.2018 द्वारा श्री मिश्र से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्री मिश्र के द्वारा अपने द्वितीय बचाव वयान में ऐसा कोई तथ्य या प्रमाण का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर उन्हें निर्दोष माना जा सके।

4. श्री मिश्र द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव वयान स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 सह यथा संशोधित नियमावली 2007 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लेते हुए विभागीय पत्रांक-1537 दिनांक 08.05.2018 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2096 दिनांक 02.11.2018 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

5 अतएव उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त श्री अजय कृष्ण मिश्र, तत्का० सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय- सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 सह यथा संशोधित नियमावली 2007 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

- 6 इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

11 जनवरी 2019

सं० 8/आ०(राज०उ०)-02-30/2015-98—श्री मनोज कुमार सिंह, तत्का० अधीक्षक उत्पाद, बेगुसराय सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध बक्सर पदस्थापन काल में अधीनस्थ कर्मियों पर अर्भ्यादित भाषा एवं जाति बोधक शब्द आदि का प्रयोग करना, बक्सर उत्पाद हाजत से अभियुक्त का फरार होना, कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा शिथिलता बरतने एवं सुरक्षा के मानकों की अनदेखी करना एवं प्रशासनिक क्षमता का अभाव, मद्य निषेध नीति के विपरीत कार्य कर उत्पाद सिपाही श्री पंजियार से शराब की मांग करना तथा उनके अवकाश को अस्वीकृत करना एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधान के प्रतिकूल आचरण तथा बेगुसराय पदस्थापन काल में सरकारी दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही एवं सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं०-1932 दिनांक 07.06.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव के पत्रांक-3166 दिनांक 15.11.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में बक्सर जिला के पदस्थापन काल में लगाये गये आरोप सं०-01, 02 एवं 04 को प्रमाणित एवं 03 को आंशिक प्रमाणित तथा बेगुसराय जिला के पदस्थापन काल में लगाये गये आरोप सं०-01 एवं 02 को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3865 दिनांक 28.11.2018 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा दिनांक 18.12.2018 को द्वितीय बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान के समीक्षोपरान्त श्री सिंह को निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 2005 के नियम-14 (V) के तहत दो वार्षिक वेतन वृद्धियों असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

5 फरवरी 2019

सं० 8/आ० (राज० उ०)—2-22/2016-413—श्री राजू कुमार मिश्र, निरीक्षक उत्पाद, मोतिहारी के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं पर्यवेक्षण कार्य का अभाव, अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण उत्पाद राजस्व की हानि होना एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल कर्तव्य के प्रति निष्ठा का पालन नहीं करना एवं अधीनस्थ सरकारी सेवक पर नियंत्रण का अभाव आदि के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-891 दिनांक 17.02.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में पूर्ण विचारोपरांत अधिसूचना सं०-4188 दिनांक 05.09.16 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (V) के तहत श्री राजू कुमार मिश्र, निरीक्षक उत्पाद, मोतिहारी के 03 (तीन) वार्षिक वेतनवृद्धियों असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

2. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री मिश्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी०नं०-17347/2016 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 27.11.2018 को निम्नांकित न्यायादेश पारित किया गया है:-

“ In both the counts, the order passed by the Special Secretary, Bihar, Patna, containing memo no. 3156 dated 05.07.2016 does not serve, accordingly the same is quashed. The matter is remanded back to the disciplinary authority to consider the case of the petitioner afresh and take decision in accordance with law within a period of two months from the date of receipt/production of a copy of this order. It is clarified that this court is not giving any opinion on the merit of the case.

With the aforesaid observations and directions, this writ petition is allowed to the aforesaid extent.

3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियमानुसार नये सिरे से कार्रवाई करने हेतु अधिसूचना सं०-4188 दिनांक 05.09.16 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

7 फरवरी 2019

सं० 8/आ०(राज० उ०)—2-11/2015/455—अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, मुंगेर का अंकेक्षण में यह प्रकाश में आया है कि उत्पाद शुल्क वसूली से संबंधित ट्रेजरी चलान में हेराफेरी कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मामले की जाँच की गयी और पाया गया कि विभिन्न पदाधिकारियों के पदस्थापन काल में फर्जी चलान के माध्यम से राजस्व क्षति पहुँचाई गयी है।

2. श्री विनोद कुमार झा, तत्का० अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद, कटिहार के विरुद्ध कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के फलस्वरूप फर्जी चालान के माध्यम से सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचना, प्रशासनिक क्षमता के अभाव के कारण अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावकारी नियंत्रण नहीं रखना एवं निजी स्वार्थ के लिए पद का दुरुपयोग कर अनुज्ञाधारियों को अनुचित लाभ पहुँचाकर सरकारी राजस्व का गबन करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-335 दिनांक 19.01.2016 यथा संशोधित संकल्प सं०-1542 दिनांक 18.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार पटना के पत्रांक-353 दिनांक 01.08.17 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप संख्या-01.02 एवं 03 को प्रमाणित पाया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3648 दिनांक 23.08.2017 द्वारा श्री झा से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

5. विभागीय पत्रांक-4641 दिनांक 15.11.2017 एवं 740 दिनांक 05.03.2018 द्वारा स्मारित करने के बावजूद श्री झा द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित नहीं किया गया। समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करा कर द्वितीय बचाव बयान की माँग की गयी, परन्तु उनके द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित नहीं किया गया।

6. इसके अतिरिक्त श्री झा के विभिन्न पदस्थापन काल में पाया गया कि वे अपने पूरे सेवा काल में कार्य के प्रति लापरवाह, उदासीन, अनुशासनहीन, और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं। पूर्व में इन्हें कई दंड अधिरोपित किये जा चुके हैं, जिसमें पदावनत करने का बृहत दंड भी है, लेकिन उनके कार्यशैली में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इस तरह के पदाधिकारियों को सेवा में बने रहने देना उचित नहीं है। अतएव पूरे सेवा काल में कर्तव्यहीनता, लापरवाही, अनुशासनहीनता, अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं राजस्वहिन के प्रतिकूल कार्यों के आवर्ती आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (पग) के अंतर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड अधिरोपित करने का विभाग द्वारा निर्णय लिया गया।

7. विभागीय निर्णय पर पत्रांक-2573 दिनांक 25.07.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/अभिमत की अपेक्षा की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने अपने पत्रांक-2635 दिनांक 31.12.2018 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया है।

8. श्री झा के विरुद्ध अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने हेतु मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया। मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-01.02.2019 में मद सं0-20 के रूप में विभागीय प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।

9. अतः मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में श्री विनोद कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद कटिहार, को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम 14 (IX) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

10. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

2 अगस्त 2019

सं0 8/आ0 (राज0उ0)-2-16/2016-2769—श्री विकास कुमार सिन्हा, तत्का0 सहायक आयुक्त उत्पाद, गया सम्प्रति सहायक आयुक्त उत्पाद, भोजपुर के विरुद्ध मे0 शिप्रा बिबरेज प्रा0 लि0 पर अधिरोपित दण्ड की राशि वसूल नहीं करने के कारण विभाग द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं राजस्व क्षति आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0-3818 दिनांक-11.08.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री श्रीकृष्ण पासवान, उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन पत्रांक-146 दिनांक 27.09.2016 समर्पित किया गया, जिसमें राजस्व क्षति एवं लापरवाही के आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के अन्तर्गत विभागीय ज्ञापांक-2976 दिनांक 11.07.2017 द्वारा द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्री सिन्हा द्वारा अपना बचाव वयान अपने पत्रांक-1770 दिनांक 08.08.2017 द्वारा समर्पित किया गया, जिसमें आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान के समीक्षोपरांत 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-4760 दिनांक 28.11.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी।

5. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-59 दिनांक 09.04.2018 द्वारा परामर्श दिया गया है कि वाद सं0-30/2016 में दिनांक 19.07.2016 को पश्चिमी न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश के आलोक में उक्त न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश पारित हो जाने के पश्चात् आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर सम्यक् समीक्षोपरान्त दण्ड अधिरोपन की कार्यवाई करते हुए आयोग के विचारार्थ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

6. श्री सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तीन वर्षों से लम्बित है। विभाग द्वारा सर्वश्री शिप्रा बिबरेज प्रा0 लि0 की 1.00 (एक) करोड़ की जमानत राशि जब्त की जा चुकी है, जो कम्पनी पर अधिरोपित अर्थदण्ड का 10 प्रतिशत अर्थात् 20.67 (लाख) से अधिक है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। सर्वश्री शिप्रा बिबरेज प्रा0 लि0 के सारे साजो-सामान एवं संयंत्र को राज्य के बाहर स्थानांतरण करने की अनुमति विभाग द्वारा दी जा चुकी है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विकास कुमार सिन्हा के विरुद्ध पूर्व प्रस्तावित दण्ड पर पुनर्विचार करते हुए श्री सिन्हा को आरोपों से मुक्त किया जाता है तथा उनके विरुद्ध संचालित विभागया कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

28 जून 2019

सं0 9/आरोप (राज0)(उ0)-2-02/2012-2254—श्री अश्विनी कुमार, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, नवादा के विरुद्ध विदेशी शराब/वीयर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उठाव नहीं होने से राजस्व की अपूरणीय क्षति, अनुज्ञप्तिधारी से मिलीभगत कर निजी लाभ उठाना एवं कर्तव्य में शिथिलता एवं उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना आदि आरोपों के लिये विभागीय संकल्प संख्या-2498 दिनांक 22.05.2012 द्वारा विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। विभागीय जॉच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी ने जॉच में श्री अश्विनी कुमार के विरुद्ध गठित तीनों आरोपों को पूर्णतया प्रमाणित पाया। जॉच प्रतिवेदन एवं श्री अश्विनी कुमार से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (xi) के परन्तुक के तहत सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 16.06.2016 के मद सं0-28 के रूप में प्रदान की गयी स्वीकृति के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3038 दिनांक 28.06.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. श्री कुमार द्वारा उक्त दण्डादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.& 610/2017 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 09.05.2017 को आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्न है :-

"The order of the disciplinary authority is non-speaking and proceeds to uphold the guilt mechanically without discussing the defence led by the petitioner and as I have observed, without dealing with the issue raised. The entire proceedings questioned in the writ petition is a bundle of illegalities and cannot be upheld and in consequence, the entire proceedings including the chargesheet, the enquiry report together with the impugned order of dismissal bearing memo No.3038 dated 28.6.2016 passed by the State Government in its Registration, Excise and Prohibition Department impugned at Annexure-28 cannot be upheld and are accordingly quashed and set aside. The petitioner is reinstated with full consequential benefits. The writ petition is allowed. In result, the review petition stands disposed of."

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक 09.05.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध विधि विभाग के परामर्श से L.P.A. No.- 1123/2017 दायर किया गया। L.P.A. No.-1123/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 11.10.2018 को अधोलिखित आदेश पारित किया गया है:-

"In view of the above and for the reasons stated above, we modify the impugned judgment and order passed by the learned Single Judge to the extent to reserve liberty in favour of the appellant-State to hold a fresh de novo enquiry in accordance with law and the rules on the same charge. The present Letters Patent Appeal is partly Allowed to the aforesaid extent.."

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A. No.- 1123/2017 में दिनांक 11.10.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग का परामर्श निम्न है:-

"The Hon'ble Division Bench only upheld the part of the order of the Hon'ble Single Judge by which the punishment of dismissal had been inflicted and enquiry proceeding after the stage of framing of the charge memo and gave liberty to the State to move afresh from the stage of framing of charges (the same charge) and hold a de novo enquiry afresh in accordance with law.

The said order being an order in favour of the State, why the State wishes to file an appeal is not manifest.

In my opinion, it is open to the State to proceed afresh i.e. on the same charge and to conduct a de novo enquiry in accordance with law."

5. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा L.P.A. No.-1123/2017 में पारित आदेश में श्री अश्विनी कुमार के विरुद्ध पूर्व गठित आरोप के आधार पर नियमानुसार नये सिरे से विभागीय कार्यवाही चलाने की छूट दी गयी है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(5) के अनुसार "जहाँ सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित शास्ति किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा निरस्त कर दी जाती है या के परिणाम स्वरूप शून्य घोषित होती है या शून्य हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकार, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार किये बिना मात्र तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो, सरकारी सेवक के विरुद्ध ऐसे आरोपों, जिन पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गयी थी, की पुनः जाँच करने का विनिश्चय करता है वहाँ सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निलम्बित किया हुआ समझा जायेगा और अगले आदेश तक निलम्बनाधीन रहेगा।"

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-1093 दिनांक 20.11.2018 के आलोक में विधि विभाग के माध्यम से श्री अश्विनी कुमार को सेवा में वहाल कर पूर्व गठित आरोपों के आधार पर नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने और श्री कुमार को उनकी बर्खास्तगी की तिथि 28.06.2016 से लगातार अगले आदेश तक निलंबित रखने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा गया।

7. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 25.06.2019 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित अनुशंसा की गयी है:-

श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना सं०-3038 दिनांक-28.06.2016 द्वारा अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड को निरस्त कर पुनः सेवा में बर्खास्तगी की तिथि 28.06.2016 से ही लगातार अगले आदेश तक निलम्बनाधीन रखते हुए सेवा में बहाल करने एवं निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किये जाने तथा L.P.A. No.- 1123/2017 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 11.10.2018 को पारित आदेश के आलोक में श्री अश्विनी कुमार के विरुद्ध पूर्व गठित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुकूल विभागीय कार्यवाही पुनः नये सिरे से प्रारंभ करने की अनुशंसा की गयी।”

8. अतः समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री अश्विनी कुमार, तत्का० अधीक्षक उत्पाद, नवादा के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना सं०-3038 दिनांक 28.06.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दंडादेश को निरस्त करते हुए उसी तिथि से सेवा में बहाल किया जाता है। श्री कुमार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (5) के तहत दिनांक 28.06.2016 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबनाधीन रहेंगे। निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय उपायुक्त मद्य निषेध, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। श्री कुमार को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

9. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

30 दिसम्बर 2019

सं० 9/आरोप(राज०)(नि०)-01-17/2012-4805—श्री अशोक कुमार मौर्य, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, खगड़िया सम्प्रति सेवा निवृत्त को उनके विभिन्न पदस्थापन कार्यालयों में अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, विभागीय निर्देश का उल्लंघन, कदाचार, अनियमितता एवं राजस्व की भारी क्षति पहुँचाने आदि गंभीर आरोपों के लिए निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-1049 दिनांक 05.04.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।

2. संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा अपने पत्रांक-716 सी०डी०ई दिनांक 30.08.2011 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में निम्नरूप से निष्कर्षित किया गया। आरोप सं०-1-जाँच में तथाकथित राजस्व क्षति का आकलन सही नहीं पाया गया एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा कदाचार एवं अनियमितता बरतने के आरोप की पुष्टि नहीं होती है (2) आरोपित पदाधिकारी द्वारा जानबुझ कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। मात्र यह कहा जा सकता है कि इन दस्तावेजों को भेजने में कुछ विलंब हुआ है। यद्यपि विलंब के बावजूद भी यह विप्रेषण **permissible** समय सीमा के अन्तर्गत था, फिर भी आज तक, सूचना के अधिकार, से प्राप्त जानकारी से स्पष्ट होता है कि कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं की गई। जबकि आरोपी को वहाँ से निलंबित हुये 01 वर्ष 08 माह की अवधि बीत चुकी है। अतएव आरोपी के कारण राजस्व की क्षति के आरोप के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है (3) आरोपित पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त विभागीय निर्देश के उल्लंघन का कोई मामला प्रमाणित नहीं होता है (4) आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। विभागीय जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में यह पाया गया कि विभागीय कार्यवाही में कतिपय बिन्दुओं का विश्लेषण नहीं हो सका है। प्रस्तुत मामला राजस्व क्षति का है। एक के बाद एक नौ दस्तावेजों के दो फसला जमीन को चौड़ के रूप में निबंधित किया गया, जिसमें 5,76,384/- (पाँच लाख छिहत्तर हजार तीन सौ चौरासी) रुपये के राजस्व की क्षति आकलित हुई। दूसरे आरोप के संबंध में जब कार्यालय में इस आशय का आवेदन प्राप्त हो गया था कि संबंधित जमीन उच्च श्रेणी की है तो भी 47(A) में रेफर करने में आरोपी पदाधिकारी द्वारा 11 माह से अधिक का विलंब किया जो गलत मंशा को दिखाता है। अतएव जाँच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक-1419 दिनांक 01.04.2014 द्वारा श्री मौर्य से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्री मौर्य द्वारा दिनांक 25.02.2013 को समर्पित बचाव के लिखित अभिकथन में असहमति के बिन्दुओं पर ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो विचारणीय हो। अतएव श्री मौर्य के बचाव का लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में विभागीय पत्रांक-3935 दिनांक 10.06.2013 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1487 दिनांक 04.10.2013 के द्वारा विभागीय प्रस्ताव में असहमति प्रदान की गयी। श्री मौर्य के विरुद्ध अन्य पदस्थापन स्थानों में निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया था:-

कार्यालय	आरोप	अधिरोपित किया गया दण्डादेश
अवर निबंधक, बहेड़ा	अनियमित निबंधन स्वीकार करने से सरकार को राजस्व क्षति	विभागीय संकल्प सं०-1549 दिनांक 25.05.11 द्वारा तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध
अवर निबंधक, नवादा	अनियमित निबंधन स्वीकार करने से सरकार का राजस्व क्षति	विभागीय संकल्प सं०-3810 दिनांक 19.12.11 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियों संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध
जिला अवर निबंधक, धनवाद	अनियमित निबंधन स्वीकार करने से सरकार को राजस्व क्षति	विभागीय अधिसूचना सं०-714 दिनांक 29.03.05 द्वारा पाँच वार्षिक वेतन वृद्धियों संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध तथा 426997/- रु० का आर्थिक सजा।

जिला अवर निबंधक, सहरसा	अनियमित निबंधन स्वीकार करने से सरकार को राजस्व क्षति	विभागीय आदेश सं०-1342 दिनांक 21.05.10 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियों असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध
---------------------------	---	---

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी ने अपने सेवाकाल के विभिन्न पदस्थापन में अनियमित कार्य किया है। श्री मौर्य द्वारा की गई अनियमितता को देखते हुए उन्हें सेवा में बने रहने देने का औचित्य नहीं रह गया था। अतएव पूर्व विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (ix) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-4371 दिनांक 09.10.2014 द्वारा श्री मौर्य को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित किया गया।

3. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री मौर्य द्वारा मा० उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. -5232/2015 दायर किया गया। उक्त याचिका में मा० उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22.01.2019 को निम्नांकित न्यायादेश पारित किया गया:-

“The notification dated 9.10.2014 is clearly unsustainable for the reasons indicated hereinabove. The order dated 9.10.2014 is therefore quashed. As a result of quashing of the order dated 9.10.2014 the order dated 29.1.2015 rejecting the petitioner’s application under Rule 24 (2) of the Bihar CCA Rules 2005 is also unsustainable inasmuch as the same merely reaffirms the illegal conclusion contained in notification dated 9.10.2014. That apart the order dated 19.1.2015 is without assigning any reason and is cryptic order which by itself is unsustainable for the said defect.

The writ petition is allowed. As a result of quashing of the impugned orders the petitioner will be entitled to all consequential benefits.

4. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध अपील दायर करने हेतु Grounds of appeal तैयार कर L.P.A. दायर करने हेतु विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया :-

“ The Departmental inquiry commissioner in his inquiry report dated 30.8.2012 had exonerated the petitioner of C.W.J.C.No 5232/2015 from the charges levelled against him. The second show cause notice issued to him by the Disciplinary authority on 5.12.2012 was quashed by order dated 13.2.2014 passed in C.W.J.C.No. 9923/2013 as the same was found to be in violation of the provisions of Rule 18(2) of the Bihar Govt. servants (C.C.A.) Rules, 2005. Thereafter by Memo No. 437 dated 9.10.2014 fresh order of punishment , that is, compulsory retirement was passed by the Disciplinary authority. The said order has been set aside vide order dated 22.1.2019 passed in C.W.J.C.No. 5232/2015 as the single Judge found that there has been gross violation of the provisions of Rule 18(6) of the aforementioned Rules, 2005 in as much as it was found that order dated 9.10.2014 passed by the Disciplinary authority does not contain any conclusion or finding on any article of charge.

In the above view of the matter, I do not find any good ground for filling L.P.A. against the writ Court order dated 22.1.2019.

7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.- 5232/2015 में दिनांक-22.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-4371 दिनांक 09.10.2014 द्वारा श्री मौर्य के विरुद्ध अनिवार्य सेवा निवृत्ति का अधिरोपित दण्ड पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ रखा गया।

8. समिति की बैठक दिनांक 02.12.2019 में सम्यक् विचारोपरांत सी०डब्लू०जे०सी०सं०-5232/2015 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22.01.2019 को पारित न्यायादेश का अनुपालन करत हुए विभागीय अधिसूचना सं०-4371 दिनांक 09.10.2014 को निरस्त किए जाने की अनुशंसा की गयी है।

9. अतः समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री अशोक कुमार मौर्य, तत्का० जिला अवर निबंधक, खगड़िया सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरुद्ध अधिरोपित दंडादेश विभागीय अधिसूचना सं०-4371 दिनांक 09.10.2014 को निरस्त किया जाता है।

10. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार वर्मा, अवर सचिव।

29 मई 2019

सं० 8/आ० (राज० उ०)-2-21/2019-1952—श्री अरुण कुमार मिश्र, तत्का० अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षक मद्य निषेध, कटिहार के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण राजस्व क्षति, अनुज्ञप्ति

का विलंब से विघटन एवं पद का दुरुपयोग करते हुए राजस्व क्षति की सूचना जिला पदाधिकारी को नहीं देना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 का उल्लंघन करना एवं विभागीय नियमावली एवं वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करने आदि आरोप में संकल्प संख्या-1489 दिनांक 16.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-189 दिनांक 22.02.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में आरोप सं0-02 को प्रमाणित एवं आरोप सं0-01 को अंशतः प्रमाणित तथा आरोप सं0-03, 04 को प्रमाणित नहीं होता है, निष्कर्षित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप एवं आरोप सं0-03 एवं 04 में विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-897 दिनांक 15.03.2018 द्वारा श्री मिश्र से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी।

3. श्री मिश्र द्वारा अपने पत्रांक-444 दिनांक 20.06.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए लगाये गए आरोपों से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया। श्री मिश्र ने अपने द्वितीय बचाव में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है।

4. संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री मिश्र से प्राप्त बचाव वयान के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2015 के नियम-14 (vi) के तहत 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-127 दिनांक 16.01.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-278 दिनांक 08.05.2019 द्वारा सम्यक् विचारोपरांत विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है। अतएव श्री मिश्र के बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (vi) के तहत 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

15 फरवरी 2019

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)-2-06/2015-564—श्री विनोद कुमार झा, तत्कालीन सहायक आयुक्त उत्पाद, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त उपायुक्त उत्पाद के विरुद्ध अवैध शराब का निर्माण, चौर्य बिक्री तथा कारोबारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में विफलता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-4491 दिनांक 07.10.2015 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम-43 (बी.) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी -सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-476 दिनांक 03.10.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-4927 अनु0, दिनांक 11.12.2017 द्वारा श्री झा से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

3. श्री झा द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान दिनांक 02.01.2018 को विभाग में समर्पित किया गया। उनके द्वारा अपने बचाव वयान में ऐसा कोई तथ्य नहीं उल्लिखित किया गया है, जिस पर विचार किया जा सके।

4. संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री झा द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान पर सम्यक् विचारोपरान्त अवैध शराब के निर्माण, चौर्य बिक्री तथा अवैध कारोबारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण में विफलता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता, प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव जैसे आदि गंभीर आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (a) के तहत उनके पेंशन की राशि से 10 : (दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक-1720 दिनांक 23.05.18 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-2636 दिनांक 31.12.2018 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव अधिक होने के कारण आनुपातिक नहीं है, का अभिमत दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत के आधार पर श्री झा का बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(a) के तहत उनके पेंशन की राशि से 5 (पांच) प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

15 फरवरी 2019

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)-2-01/2019-565—श्री मनोज कुमार सिंह, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, बेगूसराय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (1)(क)(ग) एवं (2) (क) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0-332 दिनांक 30.01.2019 द्वारा दिनांक 11.01.19 से निलंबित किया गया है। कारागार से मुक्त होने के उपरांत

श्री सिंह का निलंबन अवधि में मुख्यालय उपायुक्त उत्पाद का कार्यालय, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

27 फरवरी 2019

सं० 8/आ०(राज० नि०)-1-34/2014-746—श्री अजय कृष्ण मिश्र, तत्का० सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवा के बर्खास्त द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 24(2) के तहत पुनर्विलोकन अर्जी दायर किया गया है। श्री मिश्र के विरुद्ध अपने सेवाकाल में पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक चल अचल सम्पत्ति अर्जित करने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल आचरण करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-5479 दिनांक 16.12.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री मिश्र को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 सह यथा संशोधित नियमावली 2007 के नियम-14 (Xi) के तहत मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर अधिसूचना सं०-38 दिनांक 04.01.2019 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-24(2) के अनुसार सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी, हालांकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकेगी। श्री मिश्र द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव श्री मिश्र का पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए उनके पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 18.02.2019 में मद संख्या-12 के रूप में प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः श्री अजय कृष्ण मिश्र, तात्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमण्डल, गया सम्प्रति सेवा से बर्खास्तगी के विरुद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

1. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार वर्मा, अवर सचिव।

7 मार्च 2019

सं० 8/आ० (राज० उ०)-2-11/2017-820—श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह, तत्का० निरीक्षक उत्पाद, रोहतास सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर रहना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-1643 दिनांक 16.05.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना के पत्रांक-2595 दिनांक 24.09.18 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप सं०-01 एवं 02 को: प्रमाणित नहीं होता है, निष्कर्षित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-3760 अनु०, दिनांक 19.11.2018 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. श्री सिंह ने दिनांक 14.12.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन और आरोपी पदाधिकारी द्वारा अल्प अवधि में किये गये कार्य के मद्देनजर श्री सिंह को आरोप मुक्त करते हुए भविष्य के लिए सचेत किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार वर्मा, अवर सचिव।

7 मार्च 2019

सं० 8/आ० (राज० उ०)-2-10/2017-821—श्री किशोर कुमार साह, तत्का० प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास सम्प्रति सहायक आयुक्त उत्पाद, गया के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर रहना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-1644 दिनांक 16.05.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना के पत्रांक-2466 दिनांक-12.09.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप सं०-01 एवं 02 को: प्रमाणित नहीं होता है, निष्कर्षित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-3761 अनु०, दिनांक-19.11.2018 द्वारा श्री साह से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. श्री साह ने पत्रांक-2366 दिनांक 12.12.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन और आरोपी पदाधिकारी द्वारा अल्प अवधि में किये गये कार्य के मद्देनजर श्री साह को आरोप मुक्त करते हुए भविष्य के लिए सचेत किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार वर्मा, अवर सचिव।

7 मार्च 2019

सं० 8/आ० (राज० नि०)-1-14/2019-822—श्रीमती पूजा भारती, अवर निबंधक, फारबिसगंज (अररिया) को राजस्व क्षति, अधिनियमों, नियमों एवं सरकारी निर्देशों के विपरीत कार्य करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1)(क) के तहत निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

5 जुलाई 2019

सं० 8/आ० (राज० नि०)-1-25/2017-2405—श्री नीरज कुमार, तत्का० जिला अवर निबंधक, नालन्दा को निगरानी अन्वेषण व्यूरो, पटना के धावा दल के द्वारा दिनांक 21.07.2017 को ₹ 15000/- (पन्द्रह हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायाधिक हिरासत में भेजे जाने एवं निगरानी थाना काण्ड सं०-058/2017 दिनांक 21.07.2017 दर्ज किये जाने के कारण श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(2) (A) के तहत विभागीय अधिसूचना सं०-3322 दिनांक 02.08.2017 द्वारा दिनांक 21.07.2017 से निलंबित किया गया है तथा न्यायिक हिरासत से रिहा होने पर विभागीय अधिसूचना सं०-4151 दिनांक 26.09.2017 द्वारा पुनः निलंबित किया गया है।

2. श्री कुमार के निलंबन की अवधि 12 माह से अधिक की हो गयी है।

3. श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है।

4. श्री कुमार के अभ्यावेदन पर निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 (1) के आलोक में निलम्बनादेश निर्गत होने के तिथि से बारह माह पश्चात् दिनांक 27.09.2018 के प्रभाव से पूर्व से निर्गत 50 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता में वृद्धि करते हुए 75 प्रतिशत किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

2 अगस्त 2019

सं० 8/आ० (राज० उ०)-2-26/2016-2776—श्री प्रियरंजन, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, गोपालगंज सम्प्रति सीवान के विरुद्ध दिनांक 16.08.2016 को गोपालगंज जिला में हुई जहरीली कांड में अवैध शराब का निर्माण एवं चौर्य व्यापार पर प्रतिबंध लगाने पर असफल, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतना तथा प्रभावकारी पर्यवेक्षण एवं अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण का अभाव आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं०-345 दिनांक-25.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना द्वारा अपने पत्रांक-16 दिनांक 28.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निष्कर्षित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण, समर्पित साक्ष्यों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी पर लगाया गया आरोप सं०-01, 02 प्रमाणित नहीं होता है एवं आरोप सं०-03 आंशिक प्रमाणित होता है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से आरोप सं०-01 एवं 02 में असहमत होते हुए एवं आरोप सं०-03 में प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-539 दिनांक-14.02.2019 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई। आरोपित पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-201 दिनांक-15.02.2019 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया जिसमें आरोपों से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रियरंजन, अधीक्षक उत्पाद, गोपालगंज सम्प्रति अधीक्षक मद्य निषेध, सीवान के विरुद्ध वर्ष 2016-17 के

आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (i) के तहत " निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

17 सितम्बर 2019

सं० 9/आरोप (राज०)(उ०)-2-29/2012-3405—श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्का० निरीक्षक उत्पाद, गोपालगंज सम्प्रति निरीक्षक मद्य निषेध, खगड़िया के विरुद्ध गोपालगंज जिलान्तर्गत भारत सुगर मिल, सिधवलिया से मुख्यालय के बिना अनुमति के दो मुहरबंद बेतल में छोआ का नमूना प्राप्त कर रसायन परीक्षक, पटना को भेजने एवं संबंधित मिल को कानूनी लाभ पहुँचाने आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं०-6264 दिनांक 06.12.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी उपायुक्त उत्पाद, दरभंगा-सह-कोशी-सह-पूर्णियाँ प्रमंडल, दरभंगा ने अपने पत्रांक-119 दिनांक 24.06.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि सभी अभिलेखों, साक्ष्यों, छोआ-प्रावधानों, प्रतिपरीक्षणों एवं लिये गये बयानों के आधार पर विस्तार से विश्लेषण के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-1642 दिनांक 16.04.2014 एवं 2777 दिनांक 01.07.2014 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 07.05.2014 एवं 14.07.2014 को अपना द्वितीय बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया। बचाव बयान में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन, आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का प्रतिवेदन(पत्रांक-160 दिनांक 14.01.2013) जिसके द्वारा इस मामले में प्रतिवेदित किया है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद, निरीक्षक उत्पाद ने सामान्य प्रक्रिया के तहत छोआ का नमूना भेजा था तथा नमूना भेजने में कोई अन्यथा मंषा परिलक्षित नहीं होती है, के आधार पर श्री प्रसाद, तत्का० निरीक्षक उत्पाद के विरुद्ध गठित आरोप की पुष्टि नहीं हो पा रही है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्का० निरीक्षक उत्पाद को आरोपों से मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

6 फरवरी 2020

सं० 08/आरोप-01-26/2019,सा०प्र०-1894—श्री वीरेन्द्र नारायण पाण्डेय, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-771/11, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के विरुद्ध अनधिकृत उपस्थिति, विभागीय भू-अर्जन कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने, निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीन रवैया अपनाने, बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने एवं बिना प्रभार सौंपे उपार्जित अवकाश में प्रस्थान कर जाने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1086, दिनांक 21.01.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

विषयगत विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है तथा इसी बीच श्री पाण्डेय दिनांक 31.01.2020 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो गये हैं।

अतएव विभागीय पत्रांक-1893 दिनांक 14.06.2011 द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत स्वतः सम्परिवर्तित मानी जायेगी।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 48-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

“शुद्धि-पत्र”

10 फरवरी 2020

सं० 1/स्था० (12) 01/2019-428—पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागीय अधिसूचना सं०-279-सह-पठित ज्ञापांक-280 दिनांक 28.01.2020 में अंकित संचिका संख्या 2/स्था० (12) 01/2019 के तथा ज्ञापांक में अंकित 1/स्था० (2) 02/2019 के स्थान पर 01/स्था० (12) 01/2019 शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाय।

2. अधिसूचना के शेष बातें यथावत रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता “प्रेम”, अवर सचिव।

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

शुद्धि-पत्र

6 फरवरी 2020

सं० कारा/स्था०(अधी०)-01-14/18-1078—विभागीय संकल्प ज्ञापांक 357 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा दिनांक 03.01.2020 को मंडल कारा, हाजीपुर में एक विचाराधीन बंदी मनीष कुमार उर्फ तेलिया को कारा के अंदर एक अन्य बंदी द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने की घटना में सुरक्षा में हुई गंभीर चूक, कर्तव्यहीनता, घोर लापरवाही एवं अक्षमता के आरोप के लिए श्री रमेश कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर को निलंबित करते हुए केन्द्रीय कारा, बक्सर में संलग्न किया गया है।

उक्त संकल्प में टंकण भूल के कारण” श्री रमेश प्रसाद, अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर ” के स्थान पर श्री रमेश कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर अंकित हो गया है।

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 357 दिनांक 14.01.2020 में अंकित “श्री रमेश कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर” के स्थान पर “श्री रमेश प्रसाद, अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर” पढ़ा जाय।

3. शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 48-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 340---**I MD** Idris Uddin @ Idris Uddin S/o Gafur Uddin @ Sheikh Gafur, Vill+ Post-
Moratalab, PS-Rahui, Dist- Nalanda (803118) in my Matric Certificate my name written as Idris
Uddin after affidavit I changed my name as Md Idris Uddin. Affidavit no. 311 dated
07/01/2020.

Md Idris Uddin.

No. 341---**I SHIVEE** want to change my name as SHIVEE KASHYAP vide affidavit no.
1331 dated 17/01/20 for all future purposes. I will be known as SHIVEE KASHYAP.

Shivee.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 48-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ०)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 6/आ०-376/2006(खण्ड)सा०प्र०-1314

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

24 जनवरी 2020

निगरानी विभाग(अन्वेषण ब्यूरो), बिहार के पत्रांक-2756/अ.प.शा. दिनांक 06.12.2016 द्वारा सूचित किया गया था कि श्री एस. एम. राजू भा.प्र.से.(91) सम्प्रति निलंबित, तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के विरुद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष 2013-14 और इससे पूर्व के वर्षों में छात्रवृत्ति भुगतान में हुई अनियमितताओं के मामलों में भ्रष्टाचार अधिनियम-1988 की धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(सी) (डी) के अंतर्गत निगरानी थाना कांड संख्या-127/16, दिनांक 29.11.16 दर्ज किया गया है जो सम्प्रति अनुसंधानान्तर्गत है।

2. मामले की गंभीरता, निहित नैतिक भ्रष्टाचार एवं श्री राजू के कर्तव्य निर्वहन में संभावित असहजता को देखते हुए तथा मामला अनुसंधानान्तर्गत होने के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-3 के उपनियम-3 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री एस. एम. राजू भा.प्र.से.(1991), तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को तत्काल प्रभाव से आदेश संख्या-336 दिनांक 12.01.2017 द्वारा निलंबित किया गया है।

3. श्री राजू के निलंबन की समीक्षा प्रावधानानुसार राज्य निलंबन समीक्षा समिति द्वारा निर्धारित समय-समय पर की गई और श्री राजू के निलंबन के बरकरार रखने की अनुशंसा के आलोक में निलंबन विस्तारित करते हुए बरकरार रखा गया।

4. दो वर्ष से अधिक निलंबन बरकरार रखने संबंधी प्रावधान के संदर्भ में अनुशंसा केन्द्रीय मंत्रालय निलंबन समीक्षा समिति की समीक्षा के लिए विभागीय पत्र संख्या-16280 दिनांक 13.12.2018 द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से अनुरोध किया गया। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 11.01.2019 के पत्र के द्वारा केन्द्रीय मंत्रालय निलंबन समीक्षा समिति की समीक्षा और सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में श्री राजू का निलंबन अगले छः महीने तक बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी। उक्त अनुशंसा पर राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-1929 दिनांक 12.02.2019 के द्वारा श्री राजू के निलंबन को अगले छः माह तक बरकरार रखा गया। पुनः केन्द्रीय निलंबन समीक्षा समिति के पत्र दिनांक 15.07.2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा विचारोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-10052 दिनांक 25.07.2019 द्वारा श्री एस.एम. राजू के निलंबन को अगले छः माह तक बरकरार रखा गया।

5. श्री राजू के कदाचार के गंभीर प्रकृति को देखते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 10.01.2020 के पत्र में निहित केन्द्रीय निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत श्री एस. एम. राजू भा.प्र.से. (1991) के निलंबन को अगले छः माह तक बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।

आदेश :- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

सं० 6/आ.-52/2016-सा.प्र.-2173

संकल्प

11 फरवरी 2020

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, भा.प्र.से. (बिहार : 2005) के विरुद्ध उनके बिहार प्रशासनिक सेवा कार्यकाल में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान दायित्व की अवहेलना एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप के मामले में श्री सिंह के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम 8 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक संख्या-12275 दिनांक 21.09.2017 निर्गत करते हुए श्री सिंह से बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी थी।

2. इस विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच के समक्ष ओ.ए. संख्या- 50/583/2017 दायर किया गया। माननीय न्यायाधिकरण के दिनांक 25.10.2017 के अंतरिम आदेश के द्वारा सुनवाई की अगली तिथि तक श्री सिंह के विरुद्ध निर्गत उक्त आरोप ज्ञापन के संबंध में कार्रवाई स्थगित रखने का निदेश दिया गया। माननीय न्यायाधिकरण के दिनांक 25.10.2017 के उक्त आदेश के बाद मामले की सुनवाई नहीं हुई। इस क्रम में मामले की प्रगति के संबंध में विद्वान सरकारी अधिवक्ता से दूरभाष पर संपर्क/पत्राचार किया गया, परन्तु विद्वान सरकारी अधिवक्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस मामले के संबंध में स्टैडिंग कॉन्सिल संख्या-8, पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 10.12.2019 के पत्रा द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय आरोपित पदाधिकारी के द्वारा दायर सी.डब्लू.जे.सी. संख्या-.../2019 के रिट याचिका की प्रति प्राप्त हुई, जिससे ज्ञात हुआ कि मामले में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच द्वारा दिनांक 25.07.2019 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच के इस आदेश के द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध निर्गत विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक संख्या-12275 दिनांक 21.09.2017 के संबंध में माननीय न्यायाधिकरण के इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवेदक श्री सिंह को बचाव बयान समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया था। साथ ही, आवेदक के बचाव बयान पर 60 दिनों के अन्दर अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री सिंह के बचाव बयान विचार किये जाने का आदेश दिया गया था।

3. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच द्वारा दिनांक 25.07.2019 को अंतिम आदेश के अनुपालन में श्री सिंह द्वारा कोई बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया है और सी.डब्लू.जे.सी. संख्या-.../2019 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है। इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8 (6) (a) के अंतर्गत श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप की जाँच हेतु मुख्य जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी और इस कार्य में सहयोग के लिए स्थापना उप समाहर्ता, वैशाली को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त निर्णय के आलोक में श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी तथा स्थापना उप समाहर्ता, वैशाली को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह मुख्य जाँच आयुक्त के समक्ष इस संकल्प की प्राप्ति होने की तिथि से 10 (दस) कार्य दिवसों में अथवा 10 (दस) कार्य दिवसों के बाद विहित किसी समय या उससे अनधिक दस दिनों के अंदर किसी समय जैसा जाँच पदाधिकारी आदेश दें, स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के साथ उपस्थित होंगे।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सभी सुसंगत कागजातों यथा आरोप का मद, कदाचारिता विवरणी, साक्ष्यों आदि की प्रति के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली सम्प्रति सेवानिवृत्त तथा स्थापना उप समाहर्ता, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-26/2019,सा.प्र.०-1086

संकल्प

21 जनवरी 2020

श्री वीरेन्द्र नारायण पाण्डेय, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-771/11 के विरुद्ध जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के पदस्थापन काल में अनधिकृत अनुपस्थिति, विभागीय भू-अर्जन कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने, निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीन रवैया अपनाने, बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने एवं बिना प्रभार सौंपे उपार्जित अवकाश में प्रस्थान कर जाने संबंधी आरोपों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-626 दिनांक 07.08.2019 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा प्राप्त हुआ।

उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-15209 दिनांक 08.11.2019 द्वारा श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री पाण्डेय का स्पष्टीकरण (दिनांक 28.11.2019) प्राप्त हुआ।

श्री पाण्डेय के विरुद्ध गठित आरोप पत्र एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा पाया गया कि जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा श्री पाण्डेय से बार-बार स्पष्टीकरण पूछे जाने के बावजूद इनके कार्यकलाप में कोई सुधार नहीं हुआ तथा इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इनकी निर्वाचन कार्य में शिथिलता एवं कर्तव्यहीनता के कारण लोक सभा निर्वाचन, वर्ष 2019 की तैयारी में बाधा पहुँची।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री पाण्डेय का स्पष्टीकरण अस्वीकार करते हुए मामले की विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-17 (2) के प्रावधानों के तहत श्री पाण्डेय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री पाण्डेय से अपेक्षा की जाती है वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 15/एम 1-20/2018—306
शिक्षा विभाग

संकल्प
10 फरवरी 2020

विषय :—राज्य के विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उद्भूत बकाया भुगतान हेतु विभागीय संकल्प संख्या 591 दिनांक 06.03.2019 में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार के पत्रांक 1-7/2015-U.II(1) एवं पत्रांक 1-7/2015-U.II(2) दिनांक 02.11.2017 द्वारा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/पदाधिकारियों के सातवें वेतन पुनरीक्षण हेतु आदेश निर्गत किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए वेतन पुनरीक्षण के आलोक में शिक्षा विभागीय संकल्प संख्या 591 दिनांक 06.03.2019 द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. विभागीय संकल्प संख्या 591 दिनांक 06.03.2019 की कंडिका 21 में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उद्भूत बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया का समावेश है। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण से उद्भूत बकाया भुगतान हेतु उक्त कंडिका में प्रावधानित है कि

“राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उद्भूत बकाया राशि का भुगतान किस्तवार किए जाने हेतु शिक्षा विभाग, वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लेगा। परंतु बकाया भुगतान की जो राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली है, उसे केन्द्र सरकार से प्राप्त होने के उपरांत ही भुगतान करने पर राज्य सरकार विचार करेगी”।

3. उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के वेतन पुनरीक्षण संकल्प के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं समतुल्य सम्वर्ग के कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि में होने वाले अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार का 50% राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना है। इसके आलोक में देय बकाया राशि का 50% भुगतान हेतु विभागीय पत्रांक 2206 दिनांक 26.09.2019 द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया। परंतु केन्द्र सरकार के F.1-1/2019-U II दिनांक शून्य, अक्टूबर 2019 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि सर्वप्रथम राज्य सरकार देय बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करे, तदोपरांत केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राशि के 50% की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

4. केन्द्र सरकार के उक्त निदेश के आलोक में अब सर्वप्रथम राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार/बकाया का भुगतान किया जाना है। तदोपरांत उसका 50% राशि केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होगा।

5. उपरोक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 591 दिनांक 06.03.2019 की कंडिका 21 में शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उद्भूत बकाया भुगतान के संदर्भ में वर्णित प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित/संशोधित किया जाता है :—

“राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उद्भूत बकाया राशि का भुगतान शिक्षा विभाग, वित्त विभाग की सहमति से करेगा।”

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

सं० एल/एच०जी०-14-12/2018-1306

**गृह विभाग
(विशेष शाखा)**

संकल्प

7 फरवरी 2020

श्री अनुज कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर के विरुद्ध सुपौल पदस्थापन काल में मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं अपने अधीनस्थ कर्मों में व्यक्तिगत अभिरुची रखने संबंधी आरोप प्रपत्र-क में गठित कर मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-2631, दिनांक-18.06.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही आरंभ किये जाने की अनुशंसा की गई।

2. पूर्व में मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के ज्ञापांक-647, दिनांक-12.02.2018 द्वारा श्री कुमार से उक्त आरोपों के संबंध में आरोप प्रारूप गठित करते हुए सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। परन्तु श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण अपने कार्यालय के पत्रांक-908, दिनांक-15.10.2018 द्वारा मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को समर्पित किया गया, जो मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-675, दिनांक-24.01.2019 द्वारा विभाग में प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक-3135, दिनांक-19.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मूल प्रति वापस करते हुए महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना से समीक्षा कर स्पष्ट मंतव्य/संशोधित आरोप प्रपत्र विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

3. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-2334, दिनांक-03.05.2019 द्वारा प्राप्त मंतव्य में स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं होना प्रतिवेदित किया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रपत्र 'क' में गठित एवं अनुमोदित आरोपों की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-7655, दिनांक-18.07.2019 द्वारा आरोपित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (4) के तहत बचाव अभिकथन समर्पित किए जाने का निदेश दिया गया। आरोपित द्वारा अपना बचाव अभिकथन अपने कार्यालय के पत्रांक-649, दिनांक-05.08.2019 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया है।

5. चूंकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अनुज कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की प्रकृति गंभीर है, अतएव सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित कर मामले की जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया है। श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया है तथा उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने के लिए महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

6. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।**

सं० कारा/नि०को०(अधी०)-01-20/2019-1026

**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)**

संकल्प

5 फरवरी 2020

चूंकि बिहार-राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 21.07.2019 को जिला प्रशासन, वैशाली द्वारा मंडल कारा, हाजीपुर में की गई औचक छापेमारी में 08 मोबाईल फोन, 01 मेमोरी कार्ड एवं 5200/- रुपया नगद की बरामदगी की घटना में श्री रमेश प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर सम्प्रति निलंबित (अन्य मामले में) के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। श्री प्रसाद का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री रमेश प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर सम्प्रति निलंबित (अन्य मामले में) के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

सं० 8/आ० (राज० उ०)—02-07/2018-80
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

संकल्प

10 जनवरी 2019

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री अरविन्द कुमार, तत्का० अधीक्षक उत्पाद, वैशाली सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद, बाँका द्वारा वैशाली जिला में पदस्थापन अवधि में स्वयं के नेतृत्व में थाना—पातेपुर के मंडई डीह ग्राम में दिनांक 04.06.2017 को श्री अजित सिंह एवं श्री जगदीश सिंह के घर छापेमारी की गयी थी। छापेमारी में उत्पाद प्रदर्श के साथ—साथ उसी ग्राम के श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, पिता—स० राज कुमार सिंह, ग्राम—मंडई डीह के घर की तलाशी की गयी और उनके घर से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के विपरित अनियमित रूप से रूपया जब्त किया गया। जब्त रूपया को श्री जगदीश सिंह एवं अजीत सिंह के घर के पीछे मकई के खेत से बरामद होने का उल्लेख जब्ती सूची में दर्ज कराया गया। श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह के घर की तलाशी के बाद स्थानीय व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाकर श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह की नाबालिग पुत्री एवं उसकी सहेली को गवाह बनाया गया। अपने निजी लाभ हेतु जब्त राशि से कम राशि जब्ती सूची में दर्शाया गया। अतएव बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा—56 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम—3 का उल्लंघन आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम—17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री श्रीकृष्ण पासवान, संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—8 ए को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री अरविन्द कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप प्रपत्र—'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

सं० 8/आ० (राज० नि०)—1-20/2019-3171

संकल्प

4 सितम्बर 2019

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री विनय कुमार प्रसाद, जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण के विरुद्ध मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना एवं अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण के द्वारा पूर्वी चम्पारण के तौजी सं०—951, मौजा—वरियारपुर, थाना सं०—196 के विभिन्न खेसराओं की जमीन का हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेजों के निबंधन पर रोक लगाने का अनुरोध एवं वक्फ स्टेट सं०—1628 वरियापुर, मोतिहारी, जिला पूर्वी चम्पारण की सम्पत्ति का विवरण संज्ञान में रहने के बावजूद श्री प्रसाद द्वारा उक्त स्टेट के खाता संख्या—302 खेसरा सं०—281 कुल रकबा—6.03 डी० जमीन का चार दस्तावेजों, सं०—1400, 1401, 1402, 1403 दिनांक 02.02.2019 के माध्यम से विक्रय पत्र का निबंधन किया गया है, जो नियम के विरुद्ध है।

सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मु०) के द्वारा की गई जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि स्कोर सॉफ्ट वेयर में उक्त खेसरा संख्या की प्रविष्टि है, किन्तु दस्तावेज में अंकित गलत वार्ड संख्या को आधार मान कर दस्तावेज का निबंधन

स्वीकार किया गया है, जबकि जमीन के थाना संख्या और खेसरा संख्या का रोक सूची से मिलान किया जाना युक्ति संगत है। रोक पंजी से प्रस्तुत दस्तावेजों के थाना संख्या एवं खेसरा संख्या का मिलान नहीं करना लापरवाही का सूचक है। थाना संख्या और खेसरा संख्या का स्पष्ट उल्लेख मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के पत्र में अंकित है और जिला अवर निबंधक को दस्तावेजों के निबंधन से आठ दिन पूर्व संज्ञान में आ चुका था अतएव सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने जॉच में जिला अवर निबंधक श्री प्रसाद को दोषी पाया है।

उपर्युक्त जमीन नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित है। दस्तावेज में भूमि का किस्म व्यवसायिक अंकित है। नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर जमीनों का स्थल निरीक्षण स्वयं जिला अवर निबंधक को करने हेतु विभागीय निदेश निर्गत है। दस्तावेज में जमीन का किस्म व्यवसायिक अंकित होने के आधार पर राजस्व हित में जिला अवर निबंधक द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया जाता तो निश्चित रूप से जमीन के संबंध में जानकारी हासिल होती और इस तरह का अनियमित निबंधन नहीं हो पाता। इस प्रकार जिला अवर निबंधक द्वारा मामला संज्ञान में होने के बावजूद निबंधित किया गया है।

श्री प्रसाद का यह कार्य निबंधन अधिनियम, 1908, सरकारी निदेशों, बिहार सरकारी सेवक आचार नियामवली, 1976 के नियम-3 के प्रावधानों के प्रतिकूल आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

3 अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री विनय कुमार प्रसाद के विरुद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों के जॉच के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलाई जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है, इसमें मुख्य सचिव, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है। श्री प्रसाद के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8 ए को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री विनय कुमार प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

सं० 9/आरोप (राज०)(उ०)-02-02/2019-2833

संकल्प

6 अगस्त 2019

L.P.A. No. 1123/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 11.10.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री अश्विनी कुमार, तत्का० अधीक्षक उत्पाद, नवादा के विरुद्ध विदेशी शराब/वीयर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उठाव नहीं होने से राजस्व की अपूरणीय क्षति, अनुज्ञापिधारी से मिलीभगत कर निजी लाभ उठाना एवं कर्तव्य में शिथिलता एवं उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना आदि आरोप में पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री अश्विनी कुमार, तत्का० अधीक्षक उत्पाद, नवादा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-उपायुक्त मद्य निषेध, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना के विरुद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों के जॉच के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलाई जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है, इसमें मा० मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है। श्री कुमार के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री कुमार अमित, विशेष अधीक्षक मद्य निषेध, को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री अश्विनी कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

सं० 8/आ० (राज० उ०)-02-01/2019-2648

संकल्प

24 जुलाई 2019

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री मनोज कुमार सिंह, निलंबित अधीक्षक मद्य निषेध, मुख्यालय-उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को शराब पीने के आरोप में राजीव नगर थाना के द्वारा कांड सं०-537/18 दिनांक 26.12.2018 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाना, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 एवं आर्म्स एक्ट की धारा-25 (1-B) a, 26 दर्ज तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री ओम प्रकाश मंडल, उपायुक्त मद्य निषेध (मुख्यालय) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री सिंह के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8 ए को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री मनोज कुमार सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

सं० 8/आ० (राज० उ०)-02-07/2018-561

संकल्प

15 फरवरी 2019

श्री अरविन्द कुमार, तत्का० अधीक्षक उत्पाद, वैशाली के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-80 दिनांक 10.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है। श्री कुमार दिनांक 31.01.2019 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

2. श्री कुमार के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी०) के तहत सम्पूरित किया जाता है।

3. संकल्प की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

सं० 8/आ० (राज० उ०)-02-07/2018-81

संकल्प

10 जनवरी 2019

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री अजय शंकर सहाय, तत्का० निरीक्षक उत्पाद, वैशाली सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद, बेगुसराय द्वारा वैशाली जिला में पदस्थापन अवधि में थाना-पातेपुर के मंडई डीह ग्राम में दिनांक 04.06.2017 को श्री अजित सिंह एवं श्री जगदीश सिंह के घर छापामारी की गयी थी। छापामारी में उत्पाद प्रदर्श के साथ-साथ उसी ग्राम के श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, पिता-स्व० राज कुमार सिंह, ग्राम-मंडई डीह के घर की तलाशी की गयी और उनके घर से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के विपरित अनियमित रूप से रूपया जब्त किया गया। जब्त रूपया को श्री जगदीश सिंह एवं अजीत सिंह के घर के पीछे मकई के खेत से बरामद होने का उल्लेख जब्ती सूची में दर्ज कराया गया। श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह के घर की तलाशी के बाद स्थानीय व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाकर श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह की नाबालिग पुत्री एवं उसकी सहेली को गवाह बनाया गया। अपने निजी लाभ हेतु जब्त राशि से कम राशि जब्ती सूची में दर्शाया गया। अतएव बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-56 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 का उल्लंघन आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री अजय शंकर सहाय के विरुद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17

(2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलाई जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री श्रीकृष्ण पासवान, संयुक्त आयुक्त मध्य निषेध को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री अजय शंकर सहाय के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8 ए को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री अजय शंकर सहाय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप प्रपत्र-‘क’ के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

**सं० नि०को० रोहतास-04/2014-227(15)/रा०
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

संकल्प

13 फरवरी 2020

श्री महेश राम, तत्कालीन सहायक चकबंदी पदाधिकारी, सासाराम (रोहतास) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा दिनांक-26.08.2014 को परिवादी श्री नन्दजी प्रजापति से 4,000/- (चार हजार) रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। श्री राम के विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं०-054/2014, दिनांक-26.08.2014 दर्ज किया गया, जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-2199/अप०शा०, दिनांक-28.08.2014 से विभाग को प्राप्त हुआ। विभागीय आदेश सं०-693 (चक०), दिनांक-30.09.2014 द्वारा श्री राम को हिरासत में लिये जाने की तिथि-26.08.2014 के प्रभाव से निलंबित किया गया तथा पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-2281/अप०शा०, दिनांक-09.09.2014 से अभियोजन स्वीकृति हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-730 (नि०को०), दिनांक-15.10.2014 द्वारा श्री राम के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. अनुदेशक चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-299/चक०, दिनांक-24.03.2015 से उपलब्ध कराये गये आरोप प्रपत्र ‘क’ की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-481, दिनांक-22.04.2015 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री राम का स्पष्टीकरण दिनांक-11.05.2015 विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा अपना बचाव बयान प्रस्तुत करते हुए नन्दजी प्रजापति का आवेदन पत्र एवं मणिकान्त सिंह का सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई तथा गठित आरोपों को पूर्णतः निराधार एवं असत्य बताया गया। श्री राम द्वारा पुनः एक पूरक बचाव बयान समर्पित करते हुए कुछ दस्तावेजों की माँग की गई।

3. अनुदेशक चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-299/चक०, दिनांक-24.03.2015 से प्राप्त आरोप पत्र पूर्ण नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक-1395, दिनांक-11.12.2015 द्वारा अनुदेशक, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना से पूरक आरोप पत्र की माँग की गई। संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०), बिहार, पटना के पत्रांक-172/चक०, दिनांक-29.01.2016 द्वारा पूरक आरोप प्रपत्र ‘क’ तथा पत्रांक-443/चक०, दिनांक-11.04.2016 द्वारा संशोधित पूरक आरोप प्रपत्र ‘क’ विभाग को समर्पित किया गया।

4. विभागीय पत्रांक-645, दिनांक-09.06.2016 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग की गई। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए पूरक आरोप प्रपत्र ‘क’ एवं पत्रांक-01, दिनांक-05.01.2016 की सत्यापित प्रति की माँग की गई। इस प्रकार श्री राम द्वारा अपने विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र ‘क’ में अंकित आरोपों के संबंध में अपने स्पष्टीकरण में कुछ भी अंकित नहीं किया गया जबकि विभागीय पत्रांक-645, दिनांक-09.06.2016 द्वारा आरोप प्रपत्र ‘क’ अनुलग्नक सहित की प्रति उन्हें उपलब्ध करा दी गई थी।

5. सम्यक् विचारोपरान्त मामले के सम्यक् जाँच हेतु अपर समाहर्ता, रोहतास को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश सं०-916 (नि०को०), दिनांक-29.08.2016 द्वारा श्री राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

6. कालान्तर में अपर समाहर्ता, रोहतास-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-2158 /रा०, दिनांक-08.12.2017 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित किये गये साक्ष्य, कागजातों एवं अभिकथन के आधार पर श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित दर्शाया गया। प्रमाणित आरोपों के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-80, दिनांक-07.02.2018 द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण-पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री राम द्वारा अपना आवेदन दिनांक-22.02.2018 विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने के पूर्व कुछ दस्तावेजों की पुनः माँग की गयी। विभागीय पत्रांक-690, दिनांक-20.08.2018 द्वारा आवेदक नंदजी प्रजापति का आवेदन, श्री मणिकान्त सिंह का सत्यापन प्रतिवेदन एवं विभागीय कार्यवाही संचालन से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति संलग्न करते हुए पुनः द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु

निर्देशित किया गया है। श्री राम द्वारा पुनः द्वितीय कारण—पृच्छा समर्पित करने के बजाय अभ्यावेदन समर्पित करते हुए विभागीय कार्यवाही को अमान्य बताने का प्रयास किया गया।

7. श्री राम के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध सभी कागजातों के समीक्षोपरान्त पाया गया की आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है तथा उनके पास से रिश्वत की राशि 4,000/—(चार हजार) रुपये बरामद हुई है। आरोपी के विरुद्ध पदीय कर्तव्यों के निर्वहण में भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित पाया गया है, जिसके संबंध में आरोपी से अभ्यावेदन की माँग के बावजूद उनके द्वारा बचाव पक्ष में अभ्यावेदन समर्पित करने के बजाय विभागीय कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए द्वितीय कारण—पृच्छा देने से इनकार किया गया, जबकि आरोपी द्वारा उठाये गये सवालों के संबंध में विभाग द्वारा आवश्यक दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराया गया है। उनका यह कृत्य उनके पदीय भ्रष्ट आचरण को प्रमाणित करता है।

8. सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राम के विरुद्ध सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड विनिश्चित किया गया।

9. श्री महेश राम, तत्कालीन चकबंदी पदाधिकारी, सासाराम सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड “सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी” संबंधी संलेख पर विभागीय पत्रांक—186, दिनांक—27.01.2020 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजा गया। राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक—28.01.2020 को सम्पन्न बैठक में मद सं०—24 के रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

10. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के नियम—14 (xi) के प्रावधानों के तहत श्री महेश राम, तत्कालीन सहायक चकबंदी पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास सम्प्रति निलंबित मुख्यालय चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना को सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

श्री महेश राम से संबंधित ब्यौरे निम्नवत है:—

- | | |
|---------------------|---|
| 1. नाम | :- श्री महेश राम |
| 2. पदनाम | :- तत्कालीन सहायक चकबंदी पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास सम्प्रति निलंबित मुख्यालय चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना। |
| 3. जन्म तिथि | :- 03.10.1964 |
| 4. नियुक्ति की तिथि | :- 29.04.2011 |
| 5. स्थाई पता | :- ग्राम—मोची साई, वार्ड नं०—15, पो०—चाईबासा, थाना—मुपफसिल, जिला—पश्चिम सिंहभूम, राज्य—झारखण्ड। |

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कंचन कपूर, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 48—571+10—डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>